साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 06-12 मार्च, 2023, 2023, वर्ष-8, अंक-47

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

बजट की प्रमुख बातें

- मध्य प्रदेश के स्कूलों में सभी खाली पदों में भर्ती की जाएगी
- मध्यप्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी।
- ओरछा में रामराजा लोक का निर्माण किया जाएगा
- आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को विमान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित
- कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार किया गया
- मप्र में 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान
- मध्य प्रदेश में 3346 नई गौशालाएं खोली जाएंगी
- मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
- मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
- सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान किया गया
- मध्य प्रदेश में 11 हजार एकड़ में सुगंधित फूलों की खेती की जाएगी
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
- इंदौर पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा
- बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया गया
- घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
- हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव
- सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा
- छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा शंकर शाह के नाम पर किया जाएगा
- मप्र के सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएगी
- सागर में संत रविदास स्मारक बनेगा
- नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ का बजट
- नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान
- मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का बजट
- प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ मिला

जीरो फीसदी ब्याज पर किसानों को लोन

किसानों को जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल नुकसान होने पर किसानों को राहत पंहुचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं अन्य कार्यों के लिए भी बजट की कमी नहीं हो इसके ले पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है, ताकि कृषि कार्यों में किसानों को दिक्कत नहीं हो।

प्रमुख घोषणाएं

- महिला स्वसहायता के लिए 660 करोड़
- कृषि उपार्जन योजना 1000 करोड़
- दो साल में 17000 नए शिक्षक की भर्ती होगी
- किसान कल्याण योजना 3200 करोड़
- किसानों को 10 हजार की आर्थिक सहायता
- मप्र मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़
- 900 सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे
- खेल विभाग में 738 करोड़ रुपए
- सीएम कौशल योजना के लिए 1000 करोड़

सीएम ने कहा-यह अमृत वर्षा का नई आशा, नए विश्वास का बजट

मध्यप्रदेश को मिली शक्तिः बजट की घोषणाएं, बदल देगी प्रदेश की तस्वीर

वर्ष 2023-24 के लिए कृषि बजट 53,964 करोड़ रुपए का रखा

वित्तमंत्री ने पेश किया मप्र का बजट-कोई नया कर नहीं

खेती से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देगी सरकार बजट में विशेष प्रावधान

कृषि पर कृपा

-वित्त मंत्री ने कहा- बजट जनता की उम्मीदों का, जनता मुस्कुराएगी, लाड़ली बहना के लिए विशेष

आम जनता और किसानों के लिए उम्मीदों से भरा बजट है। बजट में जिन किसानों ने लोन लिया थे और चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनके कर्ज की भारपाई सरकार करेगी।

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिससे प्रदेश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिए 53 हजार 964 करोड़ और कृषि के लिए16 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए बजट में ढाई हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में भी ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं, कृषि विभाग प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को 40 लाख तक की इकाई लगाने पर 25 प्रतिशत अनुदान देगा। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किसानों और कृषि पर खासा फोकस किया गया है। कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए इस बार के बजट में 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- बजट में अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5,510 करोड़ का प्रावधान किया है।
- किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- सीएम कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान।
- डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 270 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 152 करोड़ का प्रावधान किया।
- चलाई जा रही योजना एसएमएएम के लिए 129 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा।
- किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया।
- सरकार गहन पशु विकास परियोजना के लिए 845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बजट में सरकार ने पौधशाला उद्यान हेतु 113 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नई आशा, नए विश्वास का बजट

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का बजट अद्भुत रहा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिभर एमपी और गरीब कल्याण का बजट है। किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सही मायने में जनता का बजट है। इस बजट के लिए जनता से भी सुझाव लिए गए। यह अमृत वर्षा का बजट है। नई आशा, नए विश्वास का बजट है। इंफ्रा के लिए पूंजीगत व्यय 56 हजार 256 करोड़ किया गया है। विकास, जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए अभूतपूर्व प्रवधान किया गया है। अब तक का यह ऐतिहासिक बजट है।

मध्य पशु पालन पर सरकार का फोकस

मध्यप्रदेश के कृषि बजट में इस बार पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पशु चिकित्सा पर विशेष फोकस दिया गया है। इसके तहत 845 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्र मत्स्य संपदा योजना के तहत बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में किसानों के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एंव आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 11 हजार 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

उपलब्धिः केंद्रीय मंत्री का एलान

यूरिया के बाद अब किसानों को मिलेगी नैनो डीएपी

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक ओर बड़ी उपलब्धि। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी भी, एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगी। यूरिया के बाद डीएपी देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। डीएपी लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है। जबकि, डीएपी का उत्पादन केवल चार से पांच मिलियन टन ही है। देश में बाकी डीएपी आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने इफको के बनाए डीएपी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है।

अभी तक बोरी में मिलती थी डीएपी

किसानों को अभी तक डीएपी बोरी में मिलती थी, जिससे इसके ढुलाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नैनो डीएपी बोतल में आने से इसे उतनी ही मात्रा में आसानी से लाया जा सकेगा। इस कदम के बाद डीएपी की कीमतों में भी कमी भी होगी। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, वह कानून है जो देश में खादों की बिक्री, मूल्य, वितरण को नियंत्रित करता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल होने से इसके व्यवसायिक रिलीज का रास्ता भी साफ होने वाला है। केंद्र के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है।

सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब नैनो यूरिया की तरह नैनो डीएपी भी आ गया है। एक बोरी की जगह एक बोतल डीएपी से ही काम हो जाएगा। किसानों को फायदा होगा। यह सस्ता भी होगा और इससे काम भी तेजी से होगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

स्कूलों के खाली पदों पर भर्ती, रामराजा लोक, एक लाख नौकरियां दी जाएंगी

लाड़ली-बहना पर लक्ष्मी वर्षा

- मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट यानी ई-बजट पेश किया
- विपक्षी सदस्यों का हंगामा, सीएम शिवराज सिंह ने की शांत रहने की अपील
- डिफाल्टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी
- बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी
- धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया
- आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से यात्रा कराया जाना प्रस्तावित
- मध्यप्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव
- प्रदेश में 3346 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा
- नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ का बजट
- नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का बजट प्रावधान
- मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का बजट
- दिव्यांग बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ का बजट
- प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। सुबह 11 बजे सदन में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों के लगातार हंगामे को देखते हुए सीएम शिवराज ने उठकर विपक्ष से कहा, बजट भाषण में हंगामा नहीं करना चाहिए। विरोध करने का यह समय नहीं है, बजट भाषण सुन लीजिए। वित्तमंत्री ने कहा, यहां कपड़े फाड़ने का काम मत करो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महंगाई बढ़ा दी गई है इसको लेकर ही विरोध हो रहा है और सभी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रसोई गैस के दाम हमने नहीं बढ़ाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अब 4.8 प्रतिशत हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है। सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है। माता के गर्भ पर पोषण की व्यवस्था, प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ियां, शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश दी जा रही है। सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। वर्ष 2007 से आरंभ लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक लाड़लियां लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। देवड़ा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट का लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की विवाहित पुत्री को भी पात्रता दी गई है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को सरल और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना की निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को देय भत्तों का सातवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण करने के लिए समिति गठित की गई है।

सीएम राइज स्कूलों के लिए 3220 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान किया गया है। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए का प्रावधान। **एमबीबीएस की 1550 सीटें बढ़ेंगी-** मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी। आयुष के 200 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर शीघ्र शुरू किए जाएंगे।

शेर की तरह दहाड़ रहे हम

वित्त मंत्री ने कहा कि जनता से चार हजार सुझाव प्राप्त हुए थे उनमें से अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक परिदृश्य में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में 16 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि चालू मूल्यों पर हुई है।

शक्ति को दे रहे ताकत

वित्त मंत्री ने कहा कि नारी के सशक्त होने पर परिवार सशक्त होता है। जिससे प्रदेश और देश सशक्त बनता है। माता के गर्भवती होने पर पोषण की व्यवस्था, कन्या के जन्म पर लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूलों में पुस्तक, गणवेश दिया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिला स्व सहायता समूह के 47 लाख सदस्यों ने न सिर्फ अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए बल्कि राज्य के लिए योगदान दिया है।

105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे

इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। 105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान किया गया।

-सीएम शिवराज बोले-मध्यप्रदेश के हर स्कूल में होगी व्यवस्था

पेट्रोल की झंझट खत्म! 12वीं में अव्वल बेटियों को मिलेगी 'ई-स्कूटी'

भोपाल। प्रधान संपादक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिका स्कूटी योजना के संदर्भ में कहा कि इस योजना के तहत बालिकाओं को ई-स्कूटी प्रदान की जाएंगी, ताकि बालिकाओं के सामने पेट्रोल का झंझट ही नहीं रहे। शिवराज ने कहा कि बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा यानी एक लाख दो हजार करोड़ से अधिक रुपए का प्रावधान आधी आबादी यानी महिलाओं व बालिकाओं के उत्थान और विकास के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बालिका स्कूटी योजना भी घोषित की गई है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक स्कूल में कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। ई-स्कूटी देने का निर्णय इसलिए किया गया है कि छात्राओं के सामने अपने शैक्षणिक संस्थान आने-जाने के लिए पेट्रोल भरवाने का झंझट नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यह योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी।

शक्तिशाली भारत के निर्माण में मप्र की होगी अहम भूमिका एक अभिनव पहलः सोशल इंपेक्ट बांड लाने का प्रावधान

कुपोषण से दिलाएंगे मुक्ति

शिवराज ने कहा कि इसी तरह खेलों का बजट लगभग तीन गुना बढ़ाकर सात सौ करोड़ रुपयों से अधिक कर दिया गया है। ढांचागत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए भी बजट राशि और बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए संचालित आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार दिए जाते हैं। इसके लिए अब बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एक हजार करोड़ के बांड जारी होगा| मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण वाला है और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की ओर से अभूतपूर्व योगदान देगा। बजट में सिंचाई हो या सड़कें, हर गरीब को छत मुहैया कराने का संकल्प हो या बिजली की बुनियादी सुविधा पूरी करना, सभी चीजों के लिए प्रावधान है। बजट में एक अभिनव पहल करते हुए सोशल इंपेक्ट बांड लाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए सामाजिक महत्व के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करने के लिए एक हजार करोड़ के बांड जारी किए जाएंगे।

कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए

कांग्रेस द्वारा लाड़ली बहना को 1500 रुपए दिए जाने पर शिवराज ने कहा कि कांग्रेस और कमल नाथ झूठ बोलते हैं। इन्हें थोड़ी शर्म तो आना चाहिए। यह वही कांग्रेस है जिसने 2017 में भी विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलने वाली राशि का भुगतान बंद कर दिया था। उनके पैसे खा गए। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल योजना और तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी। पुरानी योजनाएं बंद करने वाले और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहकर उससे मुकरने वाले झूठ की दुकान हैं। कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। उनके पास कुछ था नहीं। वित्त मंत्री जी का भाषण हो गया। सारी चीजें जनता के पास बहुत प्रभावी ढंग से जाएंगी। इसलिए अराजकता मचाओ, चिल्लाओ हंगामा करो। इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया है।

सबका होगा कल्याण

शिवराज ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप शक्तिशाली भारत के निर्माण में प्रदेश की ओर से अभूतपूर्व योगदान देगा। प्रधानमंत्री का संकल्प है देश को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का, उसके तहत मध्य प्रदेश को 550 बिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये अहम कदम है।

18302 करोड़ रुपए ऊर्जा सेक्टर के लिए प्रस्तावित किए गए

16055 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए तय

14882 करोड़ रुपए का प्रावधान नगरीय विकास के लिए

3200 करोड़ सीएम किसान कल्याण योजना के लिए

1.29 करोड़ रुपए नारी कल्याण के लिए आवंटित किए

600 करोड़ रुपए का बजट महिला स्व-सहायता के लिए

7000 करोड़ लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान

300 करोड़ रुपए के बजट आहार अनुदान के लिए

10,000 की आर्थिक सहायता किसानों को हर साल

1000 करोड़ का बजट सीएम कौशल योजना के लिए

1000 करोड़ रुपए का बजट मोटे अनाज के लिए तय

11000 एकड़ मे सुगंधित खेती को बढ़ावा देगी सरकार

738 करोड़ खेल विभाग का बजट बढ़ाकर किया गया

आर्थिक उत्थान के लिए 1 लाख 60 हजार करोड़ का प्रावधान किया

पिछले साल से 17 प्रतिशत ज्यादा बजट, गरीब-किसानों पर फोकस

दिव्यांगों-निराश्रितों के लिए 1 हजार करोड़ के सोशल इंपैक्ट बॉन्ड

पहली बार ग्रीन बजट: एक हजार सरकारी वाहनों का बंद होगा संचालन

सबका साथ...सबका विकास... सबका शिवराज

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए ग्रीन बजट भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति जारी की है। राज्य सरकार अप्रैल 2023 से इसे लागू करेगी। लगभग एक हजार सरकारी वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। देवड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा भी मूल-मंत्र है। प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत अब तक 38 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देवड़ा ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में 2.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जंगलों के बेहतरीकरण पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में दस साल पहले सिर्फ 491 मेगावॉट बिजली नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनती थी। आज यह 12 गुना बढ़कर 5,875 मेगावॉट हो चुकी है। चार हजार करोड़ की 750 मेगावॉट क्षमता की सोलर एवं विंड एनर्जी हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भूमाफिया से जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत सरकारी जमीन निर्धारित लीज पर 30 साल के स्थायी पट्टे पर दी जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में रह रहे 7.25 लाख आवासहीन परिवारों को दिसंबर 2024 तक सिर पर छत देने का लक्ष्य है।

स्वच्छता के लिए पीठ थपथपाई

देवड़ा ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंदौर लगातार छठवें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। कुल 16 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

टाइगर ही नहीं अब हम चीता स्टेट भी

वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए लैंड बैंक और हैरिटेज संपत्तियों का बैंक बनाया गया है। 15 रोप-वे बनाए जा रहे हैं, ताकि पर्यटन स्थलों की पहुंच सुगम व रोमांचक बनाई जा सके। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाकर बसाया गया है। इससे हमारा प्रदेश अब टाइगर स्टेट होने के साथ ही चीता स्टेट भी हो गया है।

अमृत 1.0 पूरी, अब सीवेज पर जोर

देवड़ा ने कहा कि अमृत 1.0 परियोजना के अंतर्गत चार हजार 154 करोड़ रुपए की लागत से 22 शहरों की जलप्रदाय तथा 10 शहरों की सीवेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं पांच छावनी परिषद में राशि 12,858 करोड़ के कार्य आगामी वर्षों में किए जाएंगे।

हवाई पट्टी विकसित करेगी सरकार

औद्योगिक निवेश, पर्यटन आदि को आकर्षित करने के लिए वायु मार्ग के परिवहन के विस्तार की आवश्यकता है। ग्वालियर और खजुराहो में विमानतल के विस्तार और विकास के कार्य प्रगति पर हैं। रीवा तथा उज्जैन की हवाई पट्टियों को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवाओं से सुगम पहुंच बनाने की योजना प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया है।

स्वच्छ के लिए 2 लाख 79 हजार 223 करोड़

ग्राम विकास के लिए सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण और विविध विकास के लिए स्थानीय निकायों को देने खातिर 3083 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपए तय किए हैं और जल जीवन मिशन के लिए 56.70 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी पहुंचाने 7331 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 2 लाख 79 हजार 223 करोड़, नवीन पात्र परिवारों के घरों में शौचालय के लिए 12789 सामुदायिक स्वच्छता परिसर और 12743 गांवों में ठोस व अपशिष्ट तरल प्रबंधन गतिविधियां शुरू की गई हैं। मनरेगा में 3500 करोड़ मजदूरी के लिए तय किए गए हैं।

23 साल में 20 गुना बढ़ा बजट

प्रदेश में पिछले 23 साल में बजट में 20 गुना वृद्धि हुई है। 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। 2022 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में पिछले साल के बजट के मुकाबले 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बजट में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए का अनुमान है। संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत संबल योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं तो 25 हजार पुलिस आवास के साथ 453 थाने और पुलिस चौकी भवन की योजना पर भी काम हो रहा है। 343 भवनों का काम पूरा हो चुका है। गृह विभाग के लिए 10298 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है जो पिछले साल से 813 करोड़ अधिक है।

स्कूलों का होगा कायकल्प

बजट में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लंबे-चौड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ का प्रावधान। इसके जरिये उच्च गुणवत्ता और संसाधनों से संपन्न सरकारी स्कूलों की स्थापना की जा रही है। 277 करोड़ पीएम श्री योजना के जरिये मौजूदा स्कूलों को आदर्श बनाने के लिए। 400 करोड़ प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज विकसित करने के लिए। 734 करोड़ प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट करने तकनीकी कॉलेज बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 687 करोड़ कॉलेजों को विकसित करने के लिए। 25 करोड़ रुपए नए नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए प्रावधान है।

300 करोड़ से अपडेट होगा ट्रेजरी सॉफ्टवेयर

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बच्चों, महिलाओ, दिव्यांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन एक हजार करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बांड जारी करेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाओं में 40 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 26087 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना में एक लाख तक की लागत के व्यक्तिमूलक और उद्यम के लिए 50 लाख तक के प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

विकास पथ का अग्रसर

- 18,242 करोड़ रुपए 28 हजार मेगावॉट बिजली की समेकित क्षमता के लिए
- 900 किमी लंबा नर्मदा प्रगति पथ जो नर्मदा नदी के समांतर चलेगा
- 299 किमी लंबा अटल प्रगति पथ जो चंबल नदी के समांतर चलेगा
- विंध्य एक्सप्रेस वे विकसित होगा। भोपाल को सिंगरौली से जोड़ा जाएगा
- 11,049 करोड़ रुपए प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर खर्च होंगे
- 10,182 करोड़ रुपए सड़कों के अपग्रेडेशन और मरम्मत पर खर्च होंगे

प्रमुख प्रावधान

- पेसा कानून के जरिये जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिया
- 50 करोड़ रुपए आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनिमिया के उन्मूलन अभियान के लिए
- 728 करोड़ रुपए जनजातीय छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
- 200 करोड़ अजजा विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए
- 60 करोड़ जनजातीय युवाओं को रोजगारमूलक योजनाओं के लिए
- 10 करोड़ देवारण्य योजना के लिए सरकार ने किए बजट में प्रावधान
- 13,000 करोड़ की ऊर्जा सब्सिडी, सिंचाई में बिजली की खपत के लिए सब्सिडी
- 3,200 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे
- 2,000 करोड़ फसल बीमा योजना के लिए। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई
- 1,491 करोड़ रुपए पशुपालन एवं गौ संवर्धन आदि योजनाओं के लिए प्रावधान
- 80 करोड़ प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण भी होगा

मप्र में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं

निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फसलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूं का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है। राज्य का कृषि-जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभक्त है। इससे कृषि उपज में विविधता दिखायी देती है। प्रदेश में 10 प्रमुख नदी घाटियां और 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले अंतर्देशीय जल निकाय, 17 हजार किलोमीटर से अधिक फैली हुई नदियां और नहरें, 60 हजार हेक्टेयर से अधिक छोटे-बड़े तालाबों से पानी की भरपूर उपलब्धता से राज्य में कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूंजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी कई कार्य किये जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्मलाइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उत्पादक सहकारी समितियां और सहकारी समितियां अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं। वर्ष 2021 में दुनिया के खाद्य प्र-संस्करण बाजार का आकार 5.7 ट्रिलियन था। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 7.60 प्रतिशत की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया प्रशांत इस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया जैसे उभरते बाजार तेजी से वैश्विक विकास को गति देंगे। बढ़ते ग्राहक आधार

के करीब होने के लिए विनिर्माण और प्र-संस्करण तेजी से इन बाजारों में जायेंगे। भारत का खाद्य उत्पादन उद्योग 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचेगा। भारत की विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन में एक मजबूत स्थिति है और इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है।

इस परिदृश्य में मध्यप्रदेश, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिये लगातार काम कर रहा है। राज्य में 8 स्थान पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भंडारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहां 3 लाख 54 हजार वर्गमीटर की कुल सीमा के साथ एक विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है। खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने फूड इनोवेशन हब विकसित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। राज्य में पहले से ही 5 प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र के लिए मूल्य श्रृंखला में मौजूदा कार्य बल को शिक्षित करने और प्रतिभाशाली कौशल बल जोड़ने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के ईतर भी प्रोत्साहनों से उद्योगों को आकर्षित कर रही है।

मध्यप्रदेश ने हाल के दिनों में कैडबरी, आईटीसी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज नामी कम्पनियों को शासन स्तर से अनुकूल नीतिगत बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर निवेश को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग समर्थक नीतियां बनायी हैं। वित्तीय मोर्चे पर, खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का डेढ़ गुना है। राज्य ने अपने निर्यात को वर्ष 2005-06 में 83 करोड़ रुपये मूल्य के 9 हजार 600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2021-22 में एक हजार 300 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग एक लाख 43 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पादों को 18 प्रतिशत से अधिक के आश्चर्यजनक सीएजीआर के साथ बढ़ाया है। एक जिला-एक उत्पाद योजना में मध्यप्रदेश ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आंवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की जलवायु और क्षमताओं के आधार पर किसानों को ऐसी उपज लगाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर

महिला समाज सुधारकों के संघर्ष को याद करते हुए

समाज के विकास और उत्थान में महिलाओं और पुरुषों का समान योगदान रहा है। अक्सर पुरुषों के योगदान की चर्चा होती है, लेकिन महिलाओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की उतनी चर्चा नहीं की जाती। महिला दिवस के अवसर पर हम आज दो ऐसी ही महान नारियों के जीवन और कार्य के बारे में जानेंगे, जिन्होंने आज से पौने दो सौ वर्ष पहले स्त्री और दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। ये दो महिलाएं सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख अपने समय की क्रांतिकारी महिलाएं थीं। दोनों ने एक साथ मिलकर शिक्षा और समाज सुधार के लिये कार्य किया। सावित्री बाई फुले के योगदान से तो हम परिचित हैं। लेकिन फातिमा शेख के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सावित्री बाई के पत्रों द्वारा हमें फातिमा शेख की जानकारी मिलती है।

सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिल्हे में नायगांव नाम में हुआ था। 1840 में सावित्री बाई का विवाह जोतिबा फुले से हुआ। जोतिबा अपनी मौसेरी बहन सगुना बाई के साथ रहते थे। विवाह के बाद जोतिबा फुले ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। खुद की पढाई के साथ साथ जोतिबा घर पर सावित्री बाई को भी पढ़ाने लगे। बहुत जल्द ही सावित्रीबाई ने मराठी व अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। इस के बाद सावित्री बाई ने स्कूली परीक्षा पास कर ली। सावत्रि बाई शिक्षा का महत्तव जान गयी थीं। सावित्रीबाई और जोतिबा चाहते थे कि उन्हीं की तरह समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अवसर मिले। उस समय दलित व पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

जोतिबा और सावित्रीबाई ने अपने मन में लडकियों के लिये विद्यालय खोलने का निश्चय कर लिया। लेकिन समस्या यह थी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिला अध्यापिका कहां से लाए जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। इस महान कार्य की ज़िम्मेदारी सावित्री बाई ने संभाली। उन्होंने मिशनरी कॉलेज से टीचर ट्रेनिग का कोर्स पूरा किया। अब वे एक प्रशिक्षित अध्यापिका बन गयीं थीं। इस तरह जोतीबा और सावित्री बाई ने पूना में सन 1848 में पहले महिला विद्यालय की नीव रखी। महिलाओं के लिये विद्यालय चलाना आसान काम ना था। शुरुआत में अभिभावक अपनी लडकियों को विद्यालय में भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। लोग लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में ही नहीं थे। अज्ञानतावश उन्होंने यह धारणा बना ली थी कि यदि लडकियों को पढ़ाया गया तो उनकी सात पीढ़ियां नरक की भागीदार बन जाएंगी। ऐसी स्थिति में लोगों को समझना बड़ा कठिन था।

इसके बावजूद सावित्री बाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे लोगो के घर-घर जाती, उन्हें प्यार से समझती। शिक्षा का महत्व बताती। उनके इस कार्य से प्रेरित होकर पूना की एक और साहसी महिला शिक्षिका फातिमा शेख सामने आयीं। फातिमा शेख के साथ

आ जाने से सावित्री बाई का हौसला दुगुना हो गया। फातिमा शेख का सम्बंध एक सामान्य मुस्लिम परिवार से था। उनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। ।अपनी बिरादरी की वह पहली पढ़ी लिखी महिला थीं। फातिमा शेख बड़े भाई उस्मान शेख के साथ पूना में ही रहती थीं। उस्मान शेख महात्मा फुले के बचपन के मित्र थे। महात्मा फुले की तरह वे भी खुले विचारों के थे। उन्हीं के प्रयास से फातिमा भी पढ़ लिख पाई थीं। फातिमा शेख के साथ जुड़ जाने से लडकियों के स्कूल में जान आ गयी।

अब लड़कियों के स्कूल का काम बड़े उत्साह के साथ चलने लगा। फातिमा और सावित्री बाई दोनों सवेरे जल्दी उठ जातीं। पहले अपने घर का काम पूरा करतीं। इसके बाद पूरा समय अपने स्कूल को देती। जोतिबा और उस्मान शेख का सहयोग भी इन्हें बराबर मिलता रहता। शुरुआत में विद्यालय में केवल छह ही लड़कियां थीं। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ने लगी। सब कुछ योजना अनुसार चल रहा था। लेकिन शहर के संभ्रांत वर्ग को लडकियों का यूं पढ़ना लिखना ठीक ना लगा। इस कार्य को शास्त्र विरोधी बताकर उन्होंने फुले परिवार का विरोध किया। इसके बावजूद सावित्री बाई अपने कार्य में जुटी रही। विरोध करने वालों ने जोतिबा के पिता गोविंदराव पर दबाव बनाया। गोविंदराव को सामाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी गयी। इस विरोध के चलते गोविंदराव ने जोतिबा से विद्यालय बंद करने या घर छोड़ देने की शर्त रखी। जोतिबा और सावित्री बाई किसी भी सूरत में अपना मिशन जारी रखना चाहते थे। पिता की बात उन्होंने नहीं मानी। अंत में उन्हें अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ा।

पूणे शहर में कोई उन्हें सहारा देने को तैयार नहीं था। सावित्री बाई को अपने घर से अधिक लडकियों के पढ़ाई की चिंता सताये जा रही थी। इधर संभ्रांत वर्ग ने फुले दंपति का सामजिक बहिष्कार कर रखा था। सामजिक बहिष्कार के डर से कोई उनकी सहयता के लिये आगे नहीं आया। फुले परिवार को धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया था। ऐसी संकट की घड़ी में महात्मा फुले के बचपन के मित्र उस्मान शेख फरिश्ता बनकर सामने आए। उस्मान शेख ने अपना निजी बाड़ा फुले परिवार के लिए खोल दिया। शेख परिवार ने सावित्री बाई और जोतिबा को सहारा ही नहीं दिया बल्कि अपने घर का एक हिस्सा स्कूल चलाने के लिए भी दे दिया। इस तरह लड़कियों का विद्यालय अब फातिमा शेख के घर से ही चलने लगा। उस्मान शेख और फातिमा को भी अपने समाज के भीतर लगातार विरोध झेलना पड़ रहा था।

सावित्री बाई की तरह ही फातिमा शेख को भी बुरा-भला कहा जाता। उन पर ताने कसे जाते, गालियां दी जाती। उन पर कीचड़, गोबर फेंका जाता, उनके कपड़े गंदे हो जाया करते। दोनों महिलाएं चुपचाप ये यातनाएं सहती रहीं। फातिमा शेख और सावित्री बाई दोनों बड़ी निडर और साहसी महिलाएं थीं। दोनों ने हार नहीं मानी, वे दूनी लगन और मेहनत के साथ लड़कियों का भविष्य संवारने में जुटी रहीं। उन्होंने 1850 में उन्होंने 'द नेटिव फीमेल स्कूल। पुणे' नामी संस्था बनाई। इस संस्था के अंतर्गत पुणे शहर के आस पास 18 विद्यालय खोल गये। उस ज़माने में महिलाओं की तरह ही दलित बच्चों के लिये भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समस्या को दूर करने के लिये महात्मा फुले ने सोसायटी फॉर द प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ महार एन्ड मांग नामक संस्था की स्थापना की इस तरह महिलाओं के साथ-साथ वंचित समाज के बच्चों के लिए भी विद्यालय की शुरुआत हुई।

फातिमा शेख ऐसी पहली मुस्लिम महिला बनी जिसने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ बहुजन समाज की शिक्षा के लिए भी काम किया। फातिमा शेख के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। सावित्री बाई के पत्रों से हमें उनकी जानकारी मिलती है। हम समझ सकते हैं, आज से दो सौ वर्ष पूर्व किसी मुस्लिम महिला का इस तरह घर की चार दीवारी से बाहर आकर समाज कार्य करना, कितने साहस का काम रहा होगा। फातिमा शेख ने सावित्री बाई के मिशन को आगे ही नहीं बढ़ाया, ब्लकि संकट की घड़ी में सदा उनके साथ खड़ी रही। सावित्री बाई की अनुपस्थिति में स्कूल प्रशासन की सारी जिम्मेदारी फातिमा शेख ही संभाला करती थी। विद्यालय में छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी छात्राएं भी अध्यापिका की भूमिका निभाने लगी।

-सरकार का दावा-भोपाल में इसी साल सितंबर में होगा ट्रायल

इंदौर-भोपाल में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 710 करोड़ रु. का प्रावधान

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोनों ही शहरों में इसी साल ट्रायल्स का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश के 2023-24 बजट में नगरीय विकास पर भी फोकस किया गया है। खासकर इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को इसी साल धरातल पर उतारने के लिए 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कम से कम पहले चरण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए बजट में 710 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इससे दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि अब तक मेट्रो की पहली लाइन के काम अब पांच हजार करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। चुनावी वर्ष होने की वजह से भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है।

हालांकि अभी काम काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन दोनों शहरों में निर्धारित समय-सीमा में ट्रायन रन शुरू करने के लिए दो शिफ्टों काम किया जा रहा है। इंदौर-भोपाल मेट्रो में प्रायोरिटी कारिडोर को विधानसभा चुनाव से पहले तैयार करने की चुनौती है, जिसके चलते बजट में 710 करोड़ की राशि जारी की गई है। इससे पटरी बिछाने के साथ इलेक्टीफिकेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। इंदौर में ट्रायल रन के लिए जो साढ़े 5 किमी का प्रायोरिटी कारिडोर बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 5 मेट्रो स्टेशन भी आएंगे। इसी तरह भोपाल मेट्रो के पांच किमी प्रायोरिटी कारिडोर में भी पांच स्टेशन बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। लिहाजा इनका भी काम रात-दिन चल रहा है। दोनो स्थानों पर प्रायोरिटी कारिडोर का वायडक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें पाई गर्डर लगातार डाली जा रही है।

900 किमी लंबा बनेगा नर्मदा प्रगति पथ

बजट में नर्मदा प्रगति पथ निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया। प्रदेश में कुल 900 किमी लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनाया जाएगा। सलकनपुर के प्रसिद्ध देवी मंदिर में श्री देवी महालोक बनाया जाएगा। सरकार ने बताया कि उसने प्रदेश की 3124 किमी की सड़कों को सुधारा। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में सीबीएसई सिलेबस

आठ वर्षों में 30 प्रतिशत बढ़ी लागत

आठ साल पहले 2014 में भोपाल मेट्रो की लागत 6941 करोड़ आंकी गई थी। इन 7 साल में डालर की कीमत बढ़ी है। वहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी खासी वृद्धि हुई है। जिस तेजी से पेट्रोलियम व अन्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट लागत कुल 30 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है। यानी लगभग 2100 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ यह 9000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इन आठ वर्षों में इसकी लागत भी 1785 करोड़ बढ़ गई है।

आकांक्षा योजना

जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 23 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

कौशल अप्रेंटिस योजना

उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व अनुभवी यूथ मेन पावर तैयार होंगे। इस योजना में 1 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 60 करोड़।

कन्या विवाह-निकाह

55 हजार रुपए हर बेटी को शादी के लिए मिलेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होगी। 80 करोड़ रुपए सेंशन किए गए हैं।

दूध उत्पादन में मप्र तीसरा

दूध उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध होने का औसत देश के औसत से ज्यादा है।

सलकनपुर में नवदुर्गा कॉरिडोर बनेगा

सलकनपुर देवी लोक में नवदुर्गा कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां 64 योगिनी प्लाजा, मणिदीप के साथ दुकानें, पार्किंग आदि भी बनाई जाएगी।

नर्सिंग की 300 सीट्स बढ़ेंगी

प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 810 एवं पोस्ट बेसिक नर्सिंग की 300 सीट्स बढ़ेंगी। आयुष्मान भारत योजना के लिए 953 करोड़ का प्रावधान है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्या मिला

प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल 56 हजार 256 करोड़। प्रदेश के समस्त रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 105 रेलवे ओव्हर बिज के साथ 334 पुलों का निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 5 हजार 500 किलो मीटर सड़क का पुनडामरीकरण। 250 किलो मीटर सड़क उन्नयन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना।

ऊर्जा को क्या मिला

4 हजार करोड़ से 750 मेगावॉट क्षमता की परियोजना की स्थापना, नीमच में 500 एमडब्ल्यू, आगर में 330 एमडब्ल्यू, शाजापुर में 450 एमडब्ल्यू के सौर पार्क का विकास। ओंकारेश्वर में 600 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना। इंदौर में सोलर पावर परियोजना से जल प्रदाय की योजना, 5 करोड़ प्रतिमाह की बचत संभावित। ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर सम्पदा 20 के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित, फैसलैस पंजीयन से पक्षकारों को पंजीयक कार्यालय जाने की आवश्यकता होगा।

एक लाख युवाओं को नौकरी

- प्रदेश में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
- एससी,एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए।

फ्लाइट से तीर्थ दर्शन

- मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के के लिए 50 करोड़ स्वीकृत।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। 358 करोड़ का बजट है।

भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क

- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रुपए कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ बचेंगे।
- भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों का कर्ज भरेगी सरकार

- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए 2500 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि योजनाओं के लिए 53,264 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।

सरकारी वाहन नहीं चलेंगे

- 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार एक हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
- मध्यप्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया।

अब 10 तक होंगे समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए पंजीयन

बढ़ी रफ्तार : समर्थन मूल्य पर फसल बेचने 13311 किसानों ने कराया पंजीयन

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज मौर्य

समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की फसल बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की रफ्तार अब बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब तक 13 हजार 311 किसानों ने समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन करा लिया है। शासन ने पंजीयन कराने की तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है, इसलिए पंजीयन की संख्या में भी ओर बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद लग रही है। दरअसल, जिले के किसान इस बार समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे कारण मंडी में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा होना बताया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से गेहू के भाव में कमी आ रही है। इसलिए किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। अब पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 2 मार्च तक श्योपुर जिले में पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 13 हजार 311 हो गई है। इनमें गेहूं के लिए 12 हजार 341, चने के लिए 1116 और सरसों की फसल विक्रय करने के लिए 3406 पंजीयन कराए गए है। बताया गया है कि अभी पंजीयन कराने से कई किसान छूट गए है, इसलिए सरकार ने पंजीयन कराने की तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है।

पिछले साल कराया था 20186 किसानों ने पंजीयन

यहां बता दें कि पिछले साल समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय करने के लिए 20 हजार 186 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। लेकिन फसल बेचने के लिए महज एक ही किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए पहुंचा था। इसके पीछे कारण मंडी में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य के भाव से ज्यादा होना था।

66 हजार हेक्टेयर में है फसल

जिले में गेहूं की फसल 66 हजार हेक्टेयर में बोई गई है। इसमें कृषि विभाग के अनुसार जिले में प्रति हेक्टेयर 45 क्विंटल गेहूं की औसत पैदावार होती है। इस लिहाज से 2.97 हजार क्विंटल गेहूं पैदा होगी।

सबसे ज्यादा पंजीयन श्योपुर तहसील में

समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन कराने में श्योपुर तहसील के किसान श्योपुर जिले में सबसे आगे है। जबकि विजयपुर तहसील के किसान सबसे पीछे है। बताया गया है कि श्योपुर तहसील में अभी तक 7 हजार 328 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं बड़ौदा तहसील में 4830, कराहल में 724, वीरपुर में 278 और विजयपुर तहसील में 151 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।

जिले में अब तक हुए पंजीयन की स्थिति तहसीलवार

तहसील	कुल पंजीयन	गेहू	चना	सरसों
श्योपुर	7328	6884	448	1829
बड़ौदा	4830	4407	608	1204
कराहल	724	678	33	107
बीरपुर	278	249	11	137
विजयपुर	151	123	16	137
कुल	13311	12341	1116	3406

नपा ने लिया निर्णय, खर्च किए जाएंगे 75 लाख

आकर्षक बनेगा शहर प्रवेश श्योपुर में लाल पत्थर से बनाए जाएंगे तीन द्वार

श्योपुर। जागत गांव हमार

कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आने के बाद अब उन्हें देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों की आमद श्योपुर जिले में होगी। पर्यटकों को श्योपुर शहर की एंट्री भव्य और सुंदर लगे,इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका तैयारियां कर रही है। इसके लिए नगर पालिका परिषद श्योपुर ने शहर के तीनो ही सड़क मार्गों पर तीन प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय लिया है, जिनको करीब 75 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बताया गया है कि यह प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बनाए जाएंगे और रात में ही दमकें, इसके लिए इनपर लाइटिंग भी कराई जाएगी। यही नहीं चीता जिला बनने के बाद श्योपुर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों का स्वागत इन भव्य गेटों पर चीतों का लोगो लगाकर किया जाएगा।

10 मीटर ऊंचे और 18 मीटर चौड़े बनेगे गेट- राजस्थानी संस्कृति स्टाइल में यह जो गेट बनाए जाएंगे, इनपर पत्थर की जाली लगी होगी, जो इनको और सुंदर बनाएगी। नपा सूत्रों ने बताया है कि प्रत्येक गेट 10 मीटर ऊंचा और 18 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसमें से प्रत्येक के निर्माण पर 25-25 लाख रुपए करीब की राशि का खर्च आना बताया गया है।

स्थल का निर्णय अध्यक्ष पार्षद करेंगे

शहर के तीनो रोड पर तीन प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं, लेकिन यह प्रवेश द्वारा कहां पर बनाए जाएंगे, यह अभी तय नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि पाली, शिवपुरी रोड के साथ कोटा-बड़ौदा रोड पर प्रवेश द्वारा निर्माण का स्थल बाद में नपाध्यक्ष और पार्षदों द्वारा किया जाएगा।

- शहर की तीनों सड़कों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, इसके लिए टेंडर बुला लिए गए हैं। हर एक एंट्री गेट का निर्माण करीब 25-25 लाख रुपए की राशि से किया जाएगा। यह गेट भव्य बनाए जाएंगे, ताकि यहां आने वाले देश और विदेश के पर्यटकों को वह आकर्षित कर सकें।

रेणु सुजीत गर्ग
नपाध्यक्ष, नपा श्योपुर

– सौगातों से तेजी से बढेंगे विकास के कदम, बढ़ेंगी सुविधाएं

तोमर के प्रयासों से बजट में चंबल-ग्वालियर क्षेत्र को मिली कई सौगात

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से मध्यप्रदेश के बजट में श्योपुर जिले सहित चंबल-ग्वालियर क्षेत्र को कई सौगातें मिली हैं। क्षेत्र में अधोसंरचना विस्तार, ग्रामीण पेयजल परियोजना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सडकों के निर्माण और जिला मार्गों के लिए करोड़ों रुपए के प्रावधान किए गए हैं। इससे जहां क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, वहीं आम लोगों का जीवन आसान बनेगा।

केंद्रीय मंत्री तोमर के प्रयासों के चलते बजट द्वारा श्योपुर जिले में ग्राम पंचायत बहरावद से मानपुर रोड बाबड़ी हनुमानजी मंदिर (ग्राम जावेदश्वर) की ओर मार्ग का निर्माण 9 करोड़ रुपए से होगा। गुरुनावदा फीडर से बोर्ड सरदार के पटपरा होते हुए चिमला तक सड़क निर्माण के लिए 6.50 करोड़ रुपए, मुरैना जिले में ग्राम झुंडपुरा शहर सबलगढ़ (एनएच 522) के लिए 28.35 करोड़ रुपए, मुरैना में ही एनएच 522 से वागचीनी मार्ग निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपए, अटार टैटरा जिला मुरैना से विजयपुर धोवनी जिला श्योपुर और मोहना ग्वालियर तक करीब 12 किमी सडक निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा, मुरैना जिले में एबी केनाल निर्मित सीसी रोड किनारे क्रश बैरियर निर्माण के लिए 36.22 करोड़ रुपए, छुलावद मोदनी ग्राम के बीच क्वारी नदी पर पुल निर्माण के लिए 14.95 करोड़ रुपए, बड़ौना गांव में आसन नदी पर रपटा निर्माण के लिए 11.85 करोड़ रुपए , अहरौली गांव में रपटा के पास उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 13.23 करोड़ रुपए और ग्राम पंचायत तरसमा में क्वारी नदी एवं आसन के संगम पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 20.13 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। ग्वालियर जिले में, ग्वालियर-भिंड मार्ग से हवाई अड्डा मार्ग निर्माण के लिए 3.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह स्व. माधवराव सिंधिया मूर्ति शताब्दी पुरम ग्वालियर से भदरौली तक लगभग 4 किलोमीटर सडक निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।

करोड़ों की सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं

चंबल-ग्वालियर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए भी बजट में करोड़ों रुपए के प्रावधान किए गए हैं। श्योपुर जिले में 270 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की कडवाल टैंक नहर रहित परियोजना पर 7.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में पेयजल उपलब्धता के लिए ग्वालियर जिले में सिरोली (128.44 लाख रुपए), बिजोली (141.59 लाख रुपए), भैंसनारी (154.34 लाख रुपए), गढ़ी (121.05 लाख रुपए), देवरीटाका (103.89 लाख रुपए), सोजना (133.47 लाख रुपए), जिगसोली (133.79 लाख रुपए), ओडापुरा (161.10 लाख रुपए), दंदोरी (108.22 लाख रुपए), केथोदा (123.76 लाख रुपए), घिरूली (195.71 लाख रुपए), बन्हेरी (103.41 लाख रुपए), बेला (106.10 लाख रुपए), कैथी (111.25 लाख रुपए), करई (158.36 लाख रुपए), रायपुर (273.54 लाख रुपए) जखा (140.56 लाख रुपए) और मुगलपुर परियोजना के लिए 136.46 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुरैना जिले में कैथरी (121 लाख रुपए), पिपरोनिया (100.28 लाख रुपए), वारा (102.04 लाख रुपए), कोडेरा (104.03 लाख रुपए), माहदेवा (106 लाख रुपए), सिकरोड़ी (109.29 लाख रुपए), बावड़ी (109.43 लाख रुपए), भुरावली (11.49 लाख रुपए), बरोठा (115.60 लाख रुपए), रंचोली (116.95 लाख रुपए), पिपडख़ेड़ा (117.57 लाख रुपए), जेतपुर (119.10 लाख रुपए), बड़वारी (120.72 लाख रुपए), बस्तोली (121.23 लाख रुपए), पारोली (126.66 लाख रुपए), बिलगांव क्वारी (130.46 लाख रुपए), कोल्हूडांडा (134.31 लाख रुपए), चचेड़ी (138.89 लाख रुपए), पचेखा (145.87 लाख रुपए), उरहेरा (165.49 लाख), माधवगढ़ (172.19 लाख), पिढ़ावली (176.98 लाख), पलपुरा (192.17 लाख), इटोरा (193.06 लाख) जाबरोल (239.54 लाख) का बजट में प्रावधान किया गया है।

श्योपुर जिले के लिए पेयजल की 69 परियोजनाएं

श्योपुर जिले में कुड़ायथा (100.63 लाख रुपए), हलगांवड़ा बुजुर्ग (102.74 लाख रुपए), महाराजपुरा (105.11 लाख रुपए), नारायणपुरा (106.48 लाख रुपए), बहरावदा (112.86 लाख रुपए), पानड़ी (113.16 लाख रुपए), गोहेड़ा (114.16 लाख रुपए), मटेपुरा (122.65 लाख रुपए), शंकरपुर (146.78 लाख रुपए), मेदावली (174.36 लाख रुपए), गांवड़ी (181.71 लाख रुपए), गोपालपुरा (190.01 लाख रुपए), बागल्दा (214.28 लाख रुपए), बड़ौदा कलां (287.55 लाख रुपए), बुढ़ेरा (224.27 लाख रुपए), मायापुर (242.40 लाख रुपए), दाउदपुर (284.69 लाख रुपए) बगवाज (558.08 लाख रुपए), रजपुरा (102.74 लाख रुपए), तलावाड़ा (104.50 लाख रुपए), आवनी (107.41 लाख रुपए), नसीरपुरा (107.80 लाख रुपए), करियादेह (107.86 लाख रुपए), सोईखुर्द (103.71 लाख रुपए), हसनपुर हवेली (109.61 लाख रुपए), आमेट (109.85 लाख रुपए), बुखारी (111.54 लाख रुपए), इच्छापुरा (113.88 लाख रुपए) रीछी (114.23 लाख रुपए), चकबमूल्या (114.56 लाख रुपए), सरजूपुरा (115.24) सहित पर्तवाड़ा, पनार, झरेर, अरोदा, ढोटी, कबरसली, भोट्पुरा, फूलदा, नागरगांवडा, आसीदा, ज्वालापुर, रत्नौद, बगडुआ, जैदा, बर्धाराम, खिरखिरी, बरोली, माकडोद, कलारना, सूसवाड़ा, जवासा, चकमजीतपुर, गोठरा, मसावनी, बुढ़ेरा, बिजरपुर, खिरखिरी, बड़ागांव, मदनपुर, नागदा, बांगरोद, बैनीपुरा, बर्धाखुर्द, बगदरी, सारन अहिरवानी, बुखारी, चेंटीखेड़ा और हांसिलपुर परियोजना के लिए करीब 60 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

-फसलों को नुकसान की आशंका: खंडवा और शाजापुर में ओले भी गिरे, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम-राजगढ़ में बारिश

मध्य प्रदेश में कई जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि

भोपाल।

प्रदेश में मौसम बिगड़ने से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हुई। कई जिलों में ओले भी गिरे। भोपाल में नर्मदापुरम रोड पर हल्की बौछारें पड़ीं, वहां शाम को करीब 45 किमी की रफ्तार से हवाएं चलीं। मंदसौर, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़ जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई। खंडवा और शाजापुर में ओले भी गिरे। मौसम विज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की स्थिति तीन-चार दिन तक बनी रह सकती है। इस दौरान कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। मौसम में इस बदलाव ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

इन जिलों में बारिश की संभावना

आने वाले दिनों में भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान ओले भी गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। हवाओं का रुख दक्षिण-पश्चिम बना हुआ है। मध्य प्रदेश में उत्तर-दक्षिण ट्रफ बना हुआ है। इस वजह से विपरीत दिशाओं में टकराव होने के कारण गरज-चमक के साथ वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी सप्ताह भर बना रह सकता है।

गेहूं का दाना काला पड़ेगा

कृषि विशेषज्ञ एवं पूर्व संचालक कृषि डॉ. जीएस कौशल ने बताया कि इस समय बारिश होने से खेतों में खड़ी सभी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है। गेहूं की फसल सूख चुकी है, पानी लगने से गेहूं का दाना काला पड़ जाएगा। इससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। सरसों की फसल भी पक चुकी है। इसकी फली भीगने के बाद सूखते ही चटक जाएगी। इससे सरसों के दाने खेत में बिखर जाएंगे। तेज हवाएं चलने से खड़ी फसल भी खेत में बिछ जाएगी। इससे भी नुकसान होगा। किसानों को जितनी जल्दी संभव हो हार्वेस्टर से फसल कटवाकर सुरक्षित रख लेनी चाहिए।

ब्रांड एंबेसडर लहरी बाई ने शिवराज से लगाई गुहार

लहरी बाई के स्टॉल में कोदो, कुटरी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज सहित कई अनाजों के भी बीज थे

सरकार! मेरे पास जमीन नहीं कहां से उगाऊं मोटा अनाज

भोपाल।

डिंडोरी की लहरी बाई मोटे अनाजों (मिलेट्स) की 60 से ज्यादा किस्मों के बीज सहेजे हुए हैं। मूलत: डिंडोरी जिले के बजाग तहसील की रहने वाली 27 साल की लहरी बाई आदिवासियों को मोटे अनाज के मुफ्त बीज देकर उनका इस्तेमाल बढ़ाने की मुहिम चला रही हैं। इंदौर में हुए जी-20 सम्मेलन में उन्हें मिलेट्स संरक्षण के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। लहरी बाई की इस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी सराह चुके हैं। लेकिन, लहरी बाई को सरकार से शिकायत भी है। उनका कहना है कि उनके पास जमीन नहीं है। खेती वन विभाग वाले उजाड़ देते हैं। बैगा लहरी बाई जबलपुर के जवाहरलाल नेहरु कृषि विद्यालय में मोटे अनाजों पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जबलपुर पहुंची थीं। यहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अपना स्टॉल भी लगाया। लहरी बाई के स्टॉल में कोदो, कुटरी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज सहित कई ऐसे अनाजों के भी बीज थे, शायद ही हो कि आपने इनका नाम सुना हो।

घूम-घूमकर मोटा अनाज जमा किए

बैगा आदिवासी लहरी बाई का कहना है कि जब मोटे अनाजों की खेती बंद होने लगी तो मेरे परिवार ने इनके बीज सहेजने का संकल्प लिया था। माता-पिता के साथ मिलकर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर में घूम-घूमकर 60 प्रजाति के मोटे अनाजों के बीज सहेज कर इसका बैंक बनाया। आदिवासियों को मुफ्त बीज देती हूं और बदले में उनकी उपज का सिर्फ एक किलो अनाज लेती हूं। चाहती हूं कि देश में मोटे अनाजों की खेती और इस्तेमाल बढ़े, ताकि लोग तंदरुस्त रह सकें। डिंडोरी की बेगा आदिवासी युवती लहरी बाई के साथ फोटो क्लिक कराती रिसर्च स्कॉलर्स की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में अच्छा काम करने वालों की पूछ-परख हमेशा बरकरार रहती है और नेक काम करने वाले समाज के लिए रॉल मॉडल, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में अच्छा काम करने वालों की पूछ-परख हमेशा बरकरार रहती है और नेक काम करने वाले समाज के लिए रॉल मॉडल, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते।

5वीं तक पढ़ी हैं लहरी बाई

लहरी बाई सिर्फ 5 क्लास तक ही पढ़ी हैं। बावजूद, इसके आज इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मुरीद हैं। लहरी बाई कई जिलों में घूम-घूमकर कई किस्म की कोदो, कुटकी, कांग को इकट्ठा किया है। देश भर में मोटे अनाज (मिलेट्स) की किस्म जितनी लहरी बाई के पास है, उतनी शायद ही किसी के पास हो। यही वजह है कि मोटे अनाज के संरक्षण करने के लिए हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई जी-20 सम्मेलन में लहरी बाई को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया और उनसे मिलने के लिए विदेश से आए मेहमानों को भी लाइन लगानी पड़ी।

वन विभाग खेती नष्ट कर देता है...

लहरी बाई को सरकार से शिकायत है। उनका कहना है कि मोटे अनाज को पैदा करने और संरक्षण देने के लिए सरकार भले ही हमारी तारीफ कर रही है, पर सरकार यह भी देखे कि जब हमारे पास जमीन नहीं होगी, तो हम मोटे अनाज को कैसे पैदा करेंगे। सरकार ने जो उपलब्धि दी है, उसे पाकर अच्छा तो लगता है, पर दुख भी है, क्योंकि वन विभाग वाले आकर हमारी खेती को नष्ट कर जाते हैं। अगर हमारे पास जमीन होगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोदो, कुटकी और कांग पैदा कर सकते हैं, पर वन विभाग हमें पट्टा देता नहीं है। लहरी बाई ने शिवराज सरकार से मांग की है कि उन्हें जमीन का पट्टा दिलवा दें, जिससे कि वे कोदो, कुटकी पैदा कर सकें।

पीएम ने की थी तारीफ

पीएम मोदी ने बीते दिनों विलुप्त होते मोटे अनाजों के बीज सहेजने वाली लहरी बाई की सराहना की थी। उनकी तारीफ में ट्वीट भी किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके इस प्रयास के कायल हैं। सीएम ने लहरी बाई की प्रशंसा करते हुए कहा था- बहन लहरी बाई मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व काम कर रही हैं। प्रदेश का गौरव बढ़ा है।

लड़ रहे बैगा आदिवासियों की लड़ाई

लहरी बाई सहित सैकड़ों बैगा आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिलाने के लिए मप्र के एक समाजसेवी बीते कई सालों से काम कर रहें है, जिनका नाम है नरेश विश्वास। समाज सेवी नरेश विश्वास बताते हैं कि वह बीते 25 सालों से बैगा आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने इस मिलेट्स बैंक की नींव लहरी बाई के पिता के साथ रखी थी। नरेश विश्वास बताते हैं कि बैगा आदिवासियों के साथ वन विभाग का व्यवहार बहुत ही खराब रहता है। बैगा आदिवासी जब कभी जंगल की जमीन पर अपनी बेशकीमती फसलों को बोते हैं, तो वन विभाग इनकी फसलों को नष्ट कर देता है। इसलिए अब सरकार से वन अधिकार पट्टा के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। नरेश विश्वास बताते हैं कि बैगा आदिवासी जब पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो फिर क्यों इनसे जमीन के दस्तावेज मांगे जाते हैं। बैगा आदिवासियों के लिए कई सालों से काम कर रहे नरेश विश्वास ने राज्य सरकार से भी कई तरह के सवाल किए हैं, उनका कहना है कि लहरी बाई को बीजों के संरक्षण के लिए सम्मान सरकार ने दिया है लेकिन कभी यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार जमीन ना होने के बावजूद भी लहरी बाई ने कैसे मोटे अनाज के बीजों को उगाया। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि लहरी भाई के पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने 60 किस्म के मोटे अनाजों को पैदा कर इसका बैंक बनाया।

मिलेट्स उत्पादन में मप्र दूसरा राज्य

मिलेट्स उत्पादन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है, जो पोषक तत्वों का खजाना हैं। केंद्र सरकार ने इसे श्रीअन्न का तमगा देकर इसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। ऐसे में लहरी बाई मिलेट्स उत्पादन बढ़ाने की दिशा में रोल मॉडल की तरह काम कर रही हैं। लहरी बाई बैगा के पास मोटे अनाजों में स्ल्हार, काटा स्ल्हार, एडी सल्हार, बड़े कोदो, लदरी कोदो, बहेरी कोदो, डोंगर कुटकी, लाल डोंगर, सिताहि कुटकी, बिरनी कुटकी, लालमडिया सहित 60 किस्म के मोटे अनाज है जो कि लहरी बाई बैगा ने संरक्षित करके रखा है। उन्होंने बताया कि इन मोटे अनाजों को केवल संरक्षित कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि इन के आयुर्वेदिक गुण और इनको इस्तेमाल करने के तरीका भी बैगा आदिवासियों का कई सालों पुराना ज्ञान है जो कि आज लहरी बैगा आदिवासी की वजह से ही समाज तक पहुंच रहा है।

सख्ती | सम्मान निधि के लिए जरूरी है ई-केवाईसी और बैंक खाते से आधार लिंक

डाकघर, सीएसी सेंटर, आधार सेंटर में सुविधा, नहीं दिख रही जागरूकता

ई-केवाईसी न आधार से खाता लिंक,1 1 हजार 333 किसान सम्मान निधि से हो रहे वंचित

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और बैंक खाते से आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया गया है। जिसमें किसानों के खाता को पटवारियों व ऐप के माध्यम से आधार से लिंक कराया गया था। लेकिन जिले में अभी भी 11 हजार 333 किसान ऐसे किसान है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हो सका है। जबकि कई किसानों को ई-केवाईसी भी नहीं हो सकी है। जिस कारण जिले के इतने सारे किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि ई-केवाईसी कराने के किसानों को डाकघर, सीएसी सेंटर, आधार सेंटर में केवाईसी कराने की सुविधा दी गई है। लेकिन इसके बाद भी जिले के किसान इस दिशा में जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल, जिले में 94 हजार 171 किसानों को सम्मान निधि के लिए विभाग ने चिन्हित किया है। इनमें से 77 हजार 108 किसानों ने अपना ई-केवाईसी करा लिया है। लेकिन अभी 17 हजार 63 किसान ई केवाईसी से वंचित है। जिले की श्योपुर और विजयपुर ऐसी तहसील है, जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने केवाईसी कराने में रुचि नहीं दिखाई है।

सबसे ज्यादा किसान श्योपुर-विजयपुर में

बताया गया है कि जिले में 78 हजार 218 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक किए जा चुके है। लेकिन अभी 11 हजार 333 बैंक खातों में आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जबकि 77 हजार 108 किसानों ने अपना ई-केवाईसी करा लिया है। वहीं कुछ तहसीलों में किसानों ने आधार लिंक कराने में रुचि नहीं दिखाई है, जिसमें सबसे ज्यादा श्योपुर और विजयपुर तहसील के किसान शामिल है। वहीं सीएससी संचालकों की माने तो बहुत से किसानों को ई-केवाईसी व आधार लिंक कराने की जानकारी नहीं है।

तहसीलवार जिले के किसानों की स्थिति

तहसील	ई-केवाईसी वाले किसान	पेंडिंग किसान	आधार लिंक नहीं
बड़ौदा	13312	2187	1792
वीरपुर	10549	1767	1213
कराहल	9379	3041	1903
श्योपुर	25180	6354	4432
विजयपुर	18688	3714	1993
कुल	77108	17063	11333

गलत जानकारी देने से भी उत्पन्न हो रही समस्या

विभागीय अधिकारियों की माने तो किसान सम्मान निधि के लिए नए पंजीयन की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन पंजीकृत किसानों के गलत जानकारी फीड कराने पर राशि आवंटन में परेशानी आ रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि किसान अपने खाते से संबधित जानकारी व सही खाता नबंर अपने नजदीगी डाकघर, सीएससी सेंटर व आधार केन्द्र में जाकर सुधार करवा सकते हैं। खाता को आधार से लिंक करने के बाद सम्मान निधि की राशि आसानी से खाते में हस्तानांतरित हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च तक ई-केवाइसी और आधार लिंक करा सकते हैं।

पीओएस मशीन खरीदने के लिए शासन से मिली बजट

अब पटवारी कराएंगे किसानों के खातों को आधार से लिंक, मिलेगी पीओएस मशीन

भोपाल। जागत गांव हमार

अब पटवारी अपने हल्के में जाकर किसानों के खातों को आधार से लिंक कराएंगे। इसके लिए पटवारियों को पीओएस मशीन दी जाएगी। पीओएस मशीन खरीदने के लिए शासन की ओर से श्योपुर जिले को 30 हजार का बजट उपलब्ध कराया गया है। इस बजट से 10 मशीने खरीदकर 2-2 मशीनें जिले की सभी तहसीलों को दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में 94 हजार 171 किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लिए चिन्हित किए गए है। मगर इनमें से 11 हजार 333 किसान ऐसे है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। वहीं कुछ किसानों की ई—केवाईसी भी नहीं हो पाई है। 11 हजार 333 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलने से शासन और प्रशासन के अधिकारी गंभीर दिख रहे है। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलने शिकायतें भी शासन-प्रशासन तक भी पहुंच रही है। ऐसे में अब शासन-प्रशासन ने तय किया है कि जिस हल्के में ज्यादा किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं है, उनमें संबंधित हल्का पटवारियों को पीओएस मशीन लेकर भेजा जाएगा। यह पीओएस मशीन पटवारियों को उनकी संबंधित तहसीलों के कार्यालयों से उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्येक तहसील को दी जाएगी 2-2 मशीन

श्योपुर जिले में पांच तहसीलें है और प्रत्येक तहसीलों को पीओएस मशीन दी जाएगी। भू-अभिलेख कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीओएस मशीन खरीदने के लिए श्योपुर जिले को 30 हजार का बजट पीओएस मशीन खरीदने के लिए शासन से मिला है। इस बजट से 10 पीओएस मशीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2-2 पीओएस मशीन पांचों तहसीलो श्योपुर, बड़ौदा, कराहल, वीरपुर और विजयपुर कार्यालयों के दी जाएगी।

- पीओएस मशीन खरीदने के लिए बजट मिल गया है। जल्द ही 10 पीओएस मशीन खरीदी जाएगी। पांचों को तहसीलों को 2-2 मशीने दी जाएगी। इन मशीनों के जरिए पटवारी अपने-अपने हल्के में पहुंचकर किसानों के खातों को आधार से लिंक कराएंगे।

अमिता सिंह तोमर, अधीक्षक, भू-अभिलेख श्योपुर

तहसीलों से मिलेगी पटवारियों को मशीन

तहसील कार्यालयों से इन मशीनों को सबसे पहले उन हल्का पटवारियों को दिया जाएगा, जिन हल्कों में सबसे ज्यादा किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए है। इसके बाद पटवारी अपने-अपने हल्कों में इस मशीन के जरिए वंचित किसानों के खातों को आधार से लिंक कराएंगे। ताकि सभी किसानों के खाते आधार से लिंक हो सके और कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधी से वंचित नहीं हो सके।

एक हजार रुपए क्विंटल बोनस देने की मांग

एक महीने में 950 रुपए क्विंटल घट गया गेहूं का भाव, अन्नदाता मायूस

खंडवा। जागत गांव हमार

सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिए जाने की वजह से कृषि उपज मंडी में गेहूं के भाव घटते जा रहे हैं। एक माह की स्थिति देखें तो गेहूं के भाव में साढ़े नौ सौ रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। एक फरवरी को मंडी में गेहूं उच्चतम 3112 रुपए क्विंटल तक बिका था।

वहीं मार्च में उच्चतम भाव 2160 रुपए क्विंटल है। पिछले दिनों ही किसानों ने गेहूं के भाव में कमी की वजह से मंडी में हंगामा किया था। गेहूं उच्चतम 2175 रुपए क्विंटल में बिका। जबकि न्यूनतम भाव 1726 और माडल भाव 2050 रुपए क्विंटल रहा। हालांकि सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2125 रुपए क्विंटल से अधिक भाव में गेहूं मंडी में बिक रहा है। बावजूद इसके किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसान संघ ने मांग उठाई है कि किसानों का गेहूं यदि तीन हजार रुपए क्विंटल से कम में बिकता है तो उसे एक हजार रुपए प्रति क्विंटल का बोनस सरकार द्वारा दिया जाए।

गेहूं का रकबा

1 लाख 87 हजार 240 हेक्टेयर है गेहूं का रकबा

2125 रुपए क्विंटल है इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य

गेहूं का भाव

2160 रुपए क्विंटल था फरवरी में गेहूं का भाव

3112 रुपए क्विंटल रहा एक मार्च को गेहूं का भाव

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)